तिब्बत देश

बीजिंग ओलंपिक–2008 : चीन के लिए मनहूस ?

बीजिंग में अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के ग्रह बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों यूरोप यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात उस जांबाज़ तिब्बती युवक तेनज़िन दोरजी से हुई जिसने 'स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट' के अपने तीन अमेरिकी साथियों के साथ 25 अप्रेल के दिन तिब्बत के एवरेस्ट बेस कैंप पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन से पहले इस टीम ने यह तैयारी कर ली थी कि इंटरनेट पर इस प्रदर्शन का उसी समय लाइव प्रसारण भी होता रहे। प्रदर्शन का लक्ष्य दुनिया को यह बताना था कि पचास साल से तिब्बत पर उपनिवेशवादी कब्जा जमाए रखने वाली चीन सरकार को ओलंपिक खेलों की मेजबानी का नैतिक अधिकार नहीं है।

प्रदर्शनकारियों ने बीजिंग ओलंपिक के खिलाफ बैनर लहराया, नारे लगाए और तिब्बत का राष्ट्रगान गाया। बैनर पर बीजिंग ओलंपिक के नारे ''वन वर्ल्ड – वन ड्रीम'' का मज़ाक उड़ाते हुए उसमे तीसरा हिस्सा ''फ्री टिबेट'' जोड़कर नया रूप दे दिया गया था ''एक दुनिया – साझा सपना – आज़ाद तिब्बत''। पहले तो दुनिया भर में फैले तिब्बत समर्थक संगठनों के सदस्य इसे इंटरनेट पर देखते रहे पर उसके कुछ मिनट बाद दुनिया के कई टीवी चैनलों पर भी इसका लाइव प्रसारण शुरू हो गया । लेकिन जब तक बीजिंग सरकार को खबर होती और तिब्बत में तैनात चीनी पुलिस वहां तक पहुंच पाती तब तक जांबाज़ प्रदर्शनकारियों की यह टीम अपना काम कर चुकी थी। इस प्रदर्शन ने दिखा दिया कि बीजिंग ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। इस प्रदर्शन का पहला असर यह हुआ कि चीन सरकार ने इस इलाके में पुलिस की पहुंच आसान करने के लिए तुरत–फुरत 198 किमी लंबी पक्की सड़क बनाने का काम भी शुरू करा दिया है। यह अलग बात है कि बहाना यह बनाया जा रहा है कि 2008 में एवरेस्ट तक ओलंपिक मशाल ले जाने के लिए यह सड़क बनायी जा रही है। बाद में आने वाली खबरें बताती हैं कि इस तरह के प्रदर्शन चीन की दीवार और बीजिंग के पुलों पर भी होने लगे हैं।

ओलंपिक खेलों के पीछे एक खास फ़िलॉसफ़ी है। एक ऐसी दुनिया में जहां समाजों या व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के लिए सदियों से सिर्फ युद्ध और हिंसा का रास्ता अपनाया जाता था, खेलों को एक नए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की पहल की गई। ओलंपिक आंदोलन को दिशा देने वाले पियरे डे कूबेरटिन का लक्ष्य दुनिया के युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षित करके एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। शर्त यह है कि खेलों में किसी तरह का भेदभाव न हो और ओलंपिक भावना हो जो दोस्ती, एकता और ईमानदारी पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चीन को 2008 के ओलंपिक खेल आयोजित करने के फैसले से पहले दुनिया भर के मानवाधिकारवादी और लोकतंत्रवादी संगठनों ने समिति को चेताया था कि चीन में जिस तरह से मानवाधिकारों और लोकतंत्र का हनन चल रहा है उसे देखते हुए चीन को यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन तब आयोजन समिति ने यह दलील देते हुए चीन को बीजिंग में ओलंपिक–2008 के आयोजन का फैसला किया था कि इस आयोजन से चीन सरकार को अपने यहां मानवाधिकारों और लोकतंत्र का सम्मान करने का उत्साहवर्द्धक कारण मिलेगा।

दुर्भाग्य से ओलंपिक समिति के इस फैसले के बाद चीन की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे इस दिशा में किसी तरह के सुधार का संकेत तो क्या यह भी नहीं दिखाते की चीनी कम्युनिस्ट शासकों की इस बारे में कोई रुचि भी है। उलटे आए दिन वहां से ओलंपिक के बारे में जारी होने वाले सरकारी फरमानों और सरकारी तंत्र की ओर से उठाए जाने वाले कदम बार–बार कुछ और ही दिखा रहे हैं। ये कदम यही सिद्ध कर रहे हैं कि ओलंपिक खेलों से पहले चीन सरकार, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके इशारों पर चलने वाला प्रशासन, पुलिस और सेना यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले कि ओलंपिक के दौरान वहां का कोई भी नागरिक घोषित सरकारी लीक से परे चलने का साहस न दिखा पाए। वहां का सरकारी तंत्र पूरी ताकत के साथ ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटा हुआ है जिसमें चीन के लोकतंत्रवादी, धार्मिक संगठन या फिर तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया और सिंकियांग जैसे उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े लोग विदेशी मेहमानों, खिलाड़ियों या विदेशी मीडिया तक न पहुंच पाएं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस बारे में की गई शिकायतों को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अनसुना करने का रवैया अपनाया हुआ है उसने चीनी शासकों के दुस्साहस को और बढ़ा दिया है। हालत यह हो चुकी है कि चीन सरकार ने अपने नागरिकों के अलावा अब विदेशी पत्रकारों, पर्यटकों और दूसरे मेहमानों पर भी ओलंपिक से जुड़े अंकुश लगाने शुरू कर दिए हैं। ओलंपिक की तैयारी पर रिपोर्टिंग करने वाले विदेशी पत्रकारों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अपनी रिपोर्टें केवल ओलंपिक विषयों तक सीमित रखनी होंगी और ओलंपिक नगर से बाहर जाने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर आम नागरिकों को भी आदेश दिए गए हैं कि विदेशी पत्रकारों से दूर रहें वरना 'राजनीतिक' परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इन पत्रकारों पर तिब्बत, सिंकियांग और दक्षिणी मंगोलिया जैसे नाजुक इलाकों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां अब केवल ऐसे विदेशी पत्रकारों को छूट दी जाती है जिन पर चीन सरकार को पूरा भरोसा है कि वे चीन की आलोचना नहीं करेंगे और सरकार के समर्थन में ही लिखेंगे। ओलंपिक खेलों की कवरेज की इच्छा वाले विदेशी टीवी स्टेशनों को भी यह बात सरकारी तौर पर बता दी गई है कि उन्हें वहां से अपनी मर्जी के मुताबिक टीवी कवरेज के सीधे प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। सीधा प्रसारण करने की इच्छा रखने वाले टीवी चैनलों को अपना सिग्नल चीनी कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजना होगा जो इन प्रसारणों को आठ मिनट की निगरानी और क्लियरेंस के बाद ही प्रसारित होने के लिए छोड़ेगा । अर्थात पूरी दुनिया से आने वाले टीवी पत्रकारों के प्रसारण उनके दर्शकों तक आठ मिनट की देरी से पहुंचेंगे। चीन सरकार की इन पाबंदियों का कई टीवी स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने कड़ा विरोध किया है।

उधर कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बीजिंग ओलंपिक तैयारियों में चीनी जनता के मौलिक अधिकारों के हनन की गंभीर घटनाओं पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनकी शिकायतों के अनुसार ओलंपिक निर्माण कार्यों में बंधुआ मजदूरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है; निर्माण के लिए भारी संख्या में लोगों के घर उजाड़े जा चुके हैं; ओलंपिक सोविनियर उत्पादन के लिए भारी पैमाने पर कैदियों और बाल मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ठेकेदारों को मजदूरों के वेतन रोककर उन्हें जबरन काम पर रहने को मजबूर किया जा रहा है।

इसमें शक नहीं कि अपनी तानाशाही जिद वाले चीनी शासकों को ओलंपिक समिति के नपुंसक अधिकारियों से पूरी शह मिल रही है। पर अपने और दूसरों के मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों के हौसले की भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तेनज़िन दोरजी का कहना है कि उनका प्रदर्शन तो केवल शुरुआत है। अभी चीन सरकार को उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो कुचले हुई चीनी नागरिकों और उपनिवेश की जंजीरों में जकड़े लोगों की फुफकार से पनप रहा है। यह ओलंपिक समिति के लिए भी चेतावनी है और चीनी शासकों के लिए भी जिनके सामने इस तूफान में सोवियत संघ की तरह टूटने या फिर लोकतंत्र के आगे सिर झुकाने और तिब्बत जैसे अपने उपनिवेशों से अपनी सम्मानजनक वापसी है के दो विकल्प हैं। उम्मीद की जाए कि बीजिंग ओलंपिक इस मायने में चीन के लिए मनहूस होने के बजाए शुभ साबित होगा।

– विजय क्रान्ति

तिब्बत में एवरेस्ट बेस कैंप पर बैनर लहराते प्रदर्शनकारी : इरादे की ताकत

एवरेस्ट बेस कैंप पर तिब्बती युवक ने फहराया क्रांति–ध्वज

चीन सरकार की नाक के नीचे किए गए प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय नेट और टीवी पर प्रसारण हुआ

तिब्बत की आजादी का समर्थन करने वाले चार अमेरिकी नागरिकों ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत के एवरेस्ट बेस कैंप पर बीजिंग ओलंपिक के खिलाफ प्रदर्शन करके चीन सरकार की नींद हराम कर दी।

'स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट' के इन चार कार्यकर्ताओं ने एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेस कैंप पर एक बैनर लहराया जिस पर बीजिंग को 2008 के ओलंपिक के आयोजन की मेजबानी का विरोध किया गया था। उन्होंने ओलंपिक समिति के इस फैसले के विरोध में नारे लगाए और तिब्बत का राष्ट्र गीत भी गाया। इस प्रदर्शन की एक रोचक बात यह रही कि भले ही चीनी अधिकारियों को इस प्रदर्शन के बारे में बहुत बाद में पता चला लेकिन तब तक इंटरनेट के रास्ते इस प्रदर्शन का प्रसारण पूरी दुनिया में होता रहा। कई देशों के टेलिविजन चैनलों ने इस प्रदर्शन को लाइव प्रसारित किया। इस प्रदर्शन के लिए ये प्रदर्शनकारी कैमरा, लैपटाप कंप्यूटर और सेटेलाइट टेलिफोनअपने साथ लेकर गए थे। बैनर लहराने और तिब्बती राष्ट्रगीत गाने का काम प्रदर्शन दल के एकमात्र तिब्बती सदस्य तेनज़िन दोरजी ने किया।

ब्रसेल्स सम्मेलन में तेनज़िन दोरजी : हम होंगे कामयाब

इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारत के मनाली में जन्मा एवं पला बढ़ा 27 साल का युवक तेनजिन दोरजी ऐसा पहला निर्वासित तिब्बती बन गया है जिसने तिब्बत वापस लौटकर चीन के खिलाफ क्रांति का झंडा लहराकर अंतराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान एक बार फिर इस ज्वलंत मुद्दे की ओर खींचा। दोरजी की तीन सहयोगियों में दो महिलाएं हैं। दोरजी के पास भी अमेरिकी नागरिकता है और वे न्यूयार्क में रहते हैं।

दोरजी तथा उनके सहयोगी प्रदर्शनकारी क्रिस्टन वेस्टबी, लारेल मैकस्थरलिन तथा शेनन सर्विस को चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और 55 घंटे तक उन्हें भोजन, पानी या गर्म कपड़े तक नहीं दिये। सर्विस ने बताया, ''हमें सोने ही नहीं दिया गया। हर घंटे बाद वे तेज रोशनी हमारे चेहरे पर फेंकते और पूछताछ शुरू कर देते .. उनके सवाल हमेशा ही लगभग एक जैसे रहते।''

ब्रसेल्स में तिब्बत समर्थकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तेनज़िन दोरजी ने विजय क्रान्ति को बताया, ''हमारे प्रदर्शन से चीनी अधिकारी इतने हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने क्या कर दिया और अब उन्हें क्या करना चाहिए। बेस कैंप से हमें गिरफ्तार करने के बाद शिगात्से तक के रास्ते में वे हमें कई पुलिस केंद्रों में ले गए। वहां वे हमसे बार–बार यही जानने की कोशिश करते रहे कि हमने यह सब किस तरह किया? हमें किन चीनी और तिब्बती नागरिकों ने मदद दी और हमें किन लोगों ने तिब्बत भेजा?'' लेकिन जब तक चीन सरकार को इस प्रदर्शन की जानकारी होती और इन अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए बेस कैंप भेजा जाता तब तक प्रदर्शन दल का एक सदस्य प्रदर्शन के टेप और रिकार्डिंग लेकर वहां से गायब हो चुका था।

♦ कुछ–खास

तेनज़िन दोरजी ने 'तिब्बत देश' के साथ अपनी बातचीत में बताया कि हम सबने चीनी अधिकारियों को धमका दिया था कि हम सब अमेरिकी नागरिक हैं। इसलिए हमारे खिलाफ कोई भी कदम सोच समझकर उठाना। दोरजी के अनुसार चीनी अधिकारियों में अमेरिका का बहुत खौफ है और वे अमेरिकी नागरिकों से साथ मार–पिटाई करने से कतराते हैं। लेकिन हिरासत के दौरान उन्हें न तो खाना दिया गया और न गर्म बिस्तर दिए गए।

ब्रसेल्स सम्मेलन के दौरान इस प्रदर्शन का विस्तृत विवरण देते हुए एसएफटी की नेता और बाहर से इस प्रदर्शन का तालमेल करने वाली सुश्री ल्हाडोन टीथांग ने बताया कि इस प्रदर्शन के लिए लंबी तैयारी की गई थी। प्रदर्शन के लिए उत्साही कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया था। उनमें से हर सदस्य प्रदर्शन के लिए जरूरी किसी न किसी पक्ष का विशेषज्ञ था। उनमें से एक इंटरनेट और फोन के रास्ते लाइव टेलिकास्टिंग करने की महारत रखता था जबकि एक कैमरा चलाने में अच्छा था। लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप में कड़ाके की सर्दी के कारण फोन और कंप्यूटर की बैटरी को गर्म रखने के लिए उन्हें आखिरी दौर में हॉट वाटर बोतलों की व्यवस्था करनी पड़ी

इन युवाओं की गिरफ्तारी की खबर फैलने के कारण चीन नहीं चाहता था कि बीजिंग ओलंपिक से पहले और किरकिरी हो। इसलिये चीनी अधिकारियों ने इन लोगों को नेपाल सीमा के रास्ते निष्कासित कर दिया। लेकिन काठमांडो में इन प्रदर्शनकारियों के कारनामों से अभिभूत लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया।

एएफपी के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय ने इन लोगों के प्रदर्शन को देश को 'विभाजित' करने के उद्देश्य वाला' बताया। चीन ने अमेरिका के समक्ष आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया है।

चीन की सरकार ने कहा है कि चीन में रहते समय अमेरिकी नागरिकों को चीनी कानूनों तथा नियमों का पालन करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियू जियानचाओ ने तिब्बत में पर्यटकों की 'अलगाववादी गतिविधियों'' की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के साथ संपर्क में है।

इस प्रदर्शन ने चीन सरकार को किस हद तक परेशान कर दिया है इसका अंदाज़ इस प्रदर्शन के बाद

तिब्बत में एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर प्रदर्शनकारी : दुनिया को संदेश

चीन सरकार द्वारा एक के बाद एक लिए गए कई फैसलों से लग जाता है। चीन सरकार ने तिब्बत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति पर ब्रेक लगाते हुए तिब्बत जाने के इच्छुक पर्यटकों को परमिट जारी करने पर कई तरह के नियंत्रण लगा दिए हैं। तिब्बत जाने वाले पर्यटकों पर कड़ी पाबंदियां लगाते हुए उन्हें केवल उन्हीं इलाकों तक सीमित रहने को कहा गया है जहां का उन्हें परमिट मिला है। इसके अलावा एवरेस्ट बेस तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा की गई है जिसके पर्यावरण खतरों पर दुनिया भर के पर्यावरणवरण विशेषज्ञों ने विरोध किया है। इसी तरह चीन में तैनात विदेशी पत्रकारों पर भी तिब्बत की यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

– विजय क्रान्ति

बीजिंग–ओलंपिक के खिलाफ अभियान का प्रतीक चिन्ह : अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन

पंचेन लामा की रिहाई के लिए दिल्ली में प्रदर्शन : चीनी आतंक के खिलाफ

पंचेन लामा के बारे में चीन द्वारा कोई जानकारी न दिये जाने पर रोष

गेदुन छ्योकि नीमा की स्थिति तिब्बत के धार्मिक चरित्र के सामने आ रहे संकट का प्रतीक बनी

11वें पंचेन लामा की स्थिति तिब्बत की धार्मिक संस्कृति के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखने के संकट का प्रतीक बन गई है। तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईटीसी) की एक रपट मौजूदा तिब्बत में धार्मिक गतिविधियों एवं विद्वानों पर कड़े होते नियंत्रण का दस्तावेज है।

गेदुन छ्योकि नीमा की मौजूदा स्थिति के बारे में सूचना देने की निरंतर अंतरराष्ट्रीय अपीलों तथा गंभीर आलोचनाओं के बावजूद चीन ने युवा पंचेन लामा की अवैध हिरासत जारी रखी है।

दलाई लामा के विशेष दूत लोडी ग्यालतसेन ग्यारी ने इस बारे में कहाः ''ऐसे समय में जबकि दलाई लामा चीन के साथ बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी नेतृत्व का एक वर्ग तिब्बत में ऐसी प्रणाली लागू करने की कोशिश में है जिससे हमारे दोनों पक्षों के बीच कोई भी समाधान असंभव और अर्थहीन होकर रह जायेगा।''

आईटीसी की उपाध्यक्ष मेरी बेथ मर्के ने कहाः ''इस रपट में शामिल तिब्बत में धर्म के बारे में चीनी सरकार के दस्तावेजों से संकेत मिलते हैं कि चीन सरकार दलाई लामा के व्यापक प्रभाव को कितनी गंभीरता से लेती है और इसलिये वह तिब्बती बौद्ध संस्कृति के 'सरकारी मध्यस्थ' की अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की ओर कितनी बेताब है।''

पिछले 12 साल से चीन सरकार की हिरासत में गुमनामी की हालत में फंसे हुए पंचेन लामा के बारे मे दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है।

इस अवसर पर ताशी लुंपो विहार तथा पंचेन लामा के लिये केंद्रीय संगठन ने अपने वक्तव्य में कहा है कि, ''ताशी लुंपो विहार के प्रधान तथा सभी भिक्षु परमपावन पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना करते हैं। हालांकि, हम इस वर्षगांठ को बेहद भारी मन से मना रहे हैं।

पंचेन लामा के बारे में सूचना देने की निरंतर अंतरराष्ट्रीय अपीलों तथा गंभीर आलोचनाओं के बावजूद चीन ने युवा पंचेन लामा की अवैध हिरासत जारी रखी है और वह उन अपीलों को मानने से इनकार करता रहा है।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा पंचेन लामा को राजनीतिक दुराग्रह का शिकार बनाया जायेगा। चीन की सरकार ने निर्दोष पंचेन लामा गेदुन छ्योकि नीमा का बिना आरोपों के अपहरण कर लिया तथा उन्हें हिरासत में रख रखा है। इससे भी आगे बढ़ते हुए चीन ने एक अन्य किशोर ग्यालत्सेन नोरबू को पंचेन लामा को ' चीन स्वीकृत' संस्करण के रूप में नियुक्त कर दिया है। ये कदम चीनी सरकार के राजनीति हितों को साधने के लिये परम पावन दलाई लामा की हैसियत घटाने तथा तिब्बती लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश भर हैं।

तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में पंचेन लामा महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं। तिब्बती नागरिक उन्हें बुद्ध के सर्वोच्च अवतारों में गिनते हैं। विशेषकर दसवें पंचेन लामा ने अपना सारा जीवन तिब्बती लोगों के अधिकार तथा आजादी के लिये लड़ने में लगा दिया। चीन की सरकार द्वारा तिब्बती लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों की निंदा करने और स्थिति को सुधारने की मांग को चीन सरकार के सर्वोच्च नेताओं तक पहुंचाने में उनका योगदान अद्वितीय रहा है।

चीन ने मौजूदा वास्तविकताओं पर विचार किये बिना तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं पर कान धरे बिना ही तिब्बत में अपनी दिग्भ्रमित, कठोर नीति को जारी रखा है।

परम पावन दलाई लामा द्वारा समन्वय के लिये अपनाये गये सकारात्मक रुख को साझा समझ के साथ तिब्बती मुद्दे के समाधान के लिये चीन को अच्छे विश्वास तथा सकारात्मक रवैये के साथ स्वीकार करना चाहिए।

हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि चीन की सरकार इस दिशा में पहल करेगी। इस तरह से हम चीन सरकार से पंचेन लामा तथा उनके परिवार की मौजूदा स्थिति

के बारे में जानकारी मुहैया कराने और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।''

मानवाधिकार तथा लोकतंत्र के लिये तिब्बती केंद्र का वक्तव्य :

आज तिब्बत के ग्यारहवें पंचेन लामा गेदुन छ्योकि नीमा का 18 वां जन्मदिन है जो गत 12 साल से अपने परिवार के साथ लापता हैं।

गत एक दशक में विभिन्न सरकारों एवं स्वतंत्र संगठनों ने चीन के अधिकारियों पर दबाव डाला कि पंचेन लामा तथा उनके परिवार की स्थिति का खुलासा किया जाये। खेदजनक है कि चीनी अधिकारी इस पर ध्यान देने के बजाए पंचेन लामा तथा उनके परिवार तक किसी को नहीं पहुंचने देने के अनेक कारण अब तक गिनाते आ रहे हैं।

गत वर्ष रायटर्स समाचार एजेंसी द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब में चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने कहा कि परिवार की ओर से परेशान न किए जाने की इच्छा का आदर करते हुए चीन ने विदेशी संगठनों या मीडिया के साथ उनकी मुलाकात की व्यवस्था नहीं की है।

इसी तरह 1997 में भी चीन ने संयुक्त राष्ट्र के संम्बद्ध एक संगठन की मांग पर कहा था कि गेदुन छ्योकि नीमा एवं उनके परिवार ने बाहरी लोगों से परेशान नहीं करने का आग्रह किया है। सितंबर, 2005 में चीन के अधिकारियों ने यूएन स्पेषल रिपोर्टर आन फ्रीड्म आफ रिलिजन ओर बिलीफ को सूचित किया कि गेदुन छ्योकि नीमा ' बेहतर तथा स्वस्थ हैं और किसी अन्य किशोर की भांति ही सामान्य एवं सुखद जीवन जी रहे हैं। वे अच्छी सांस्कृतिक षिक्षा भी पा रहे हैं।''

एक साल बाद चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र में दी गई सूचना में यहां तक दावा किया गया कि गेदुन छ्योकि तो पंचेन लामा ही नहीं है बल्कि ' एक सामान्य तिब्बती बालक ' है। यह अलग बात है कि चीन इस बालक तक स्वतंत्र विषेषज्ञों की पहुंच एवं उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी लेने की अनुमति देने से सदैव आनाकानी करता रहा है।

ताजा घटनाक्रम में मानवाधिकार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पंचेन लामा की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता का इजहार किया है। इस संगठन ने चीन की सरकार से मांग की है कि पंचेन लामा को आजादी से कहीं आने जाने की अनुमति दी जाये। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् की बैठक के दौरान 15 गैर सरकारी संगठनों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें ग्यारहवें पंचेन लामा के लापता रहने को एक निरंतर चलने वाला अपराध करार दिया गया है।

मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त श्रीमती लुई आर्बर ने 29 अगस्त से 2 सितंबर 2005 के दौरान चीन की अपनी सरकारी यात्रा के समय गेदुन छ्योकि नीमा का मामला चीनी अधिकारियों के समक्ष उठाया।

इसी तरह धार्मिक आजादी पर संयुक्त राष्ट्र की विषेष दूत अस्मां जहांगीर भी नौ जनवरी 2005 को अपनी चिंताओं को प्रकट कर चुकी हैं। चीनी गणतंत्र (पीआरसी) ने 29 अगस्त 1990 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये और 2 मार्च 1992 को इसकी पुष्टि की। लेकिन चीन में पंचेन लामा को निरंतर हिरासत में रखा जाना उक्त सम्मेलन के उल्लंघन का स्पष्ट नमूना है। इसके अलावा यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखे जाने का नमूना भी है। यह तिब्बत में सतत धार्मिक उत्पीड़न को भी रेखांकित करता है।

मानवाधिकार तथा लोकतंत्र के लिये तिब्बती केंद्र, टीसीएचआरडी पंचेन लामा तथा उनके परिवार के निरंतर लापता होने तथा हिरासत में होने पर गहरी चिंता जताता है तथा उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। यह संगठन पंचेन लामा की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर मांग उठाने और इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का काम बहुत लगन के साथ करता आ रहा है।

इसके अलावा संगठन अंतरराष्ट्रीय निकायों का आह्वान करता है कि वे चीन के अधिकारियों पर पंचेन लामा के बारे में जानकारी देने का दबाव बनायें और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ उन्हें मिलने की अनुमति देने का दबाव बनायें।

पीआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि तिब्बती लोगों की धार्मिक आजादी का आदर हो जिसमें धार्मिक गुरुओं के चयन का अधिकार भी है।

इसी तरह इंटरनेशनल टिबेट इंडेपंडेंस मूवमेंट ने भी ग्यारहवें पंचेन लामा की रिहाई की मांग की है। संगठन ने पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर जारी वक्तव्य में कहा है कि उनकी रिहाई होने तक हम आराम नहीं करेंगे। हम उनकी आजादी के लिये सक्रियता एवं आक्रामकता के साथ लड़ेंगे।

संगठन ने अपनी मांग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये न्यूयार्क शहर तथा फिलाडेल्फिया के बीच यात्रा निकालने की भी योजना है।

चीनी गणतंत्र (पीआरसी) ने 29 अगस्त 1990 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये और 2 मार्च 1992 को इसकी पुष्टि की। लेकिन चीन में पंचेन लामा को निरंतर हिरासत में रखा जाना उक्त सम्मेलन के उल्लंघन का स्पष्ट नमूना है। इसके अलावा यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखे जाने का नमूना भी है।

तिब्बत के समर्थन में वाशिंगटन में प्रदर्शन : मानवाधिकारों पर चिंता

चार गैर सरकारी संगठनों ने तिब्बत में सांस्कृतिक संहार के प्रति किया आगाह

तिब्बती भाई बंधु अपनी ही मातृभूमि में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं

यह वक्तव्य तिब्बत में सामने आ रही नयी समस्या को रेखांकित करता है। चीन की सरकार लोगों को बड़े पैमाने पर तिब्बत में स्थानांतरित कर रही है जिसके चलते वहां के मूल लोगों के समक्ष एक नस्ल के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखना भी चुनौती बनता जा रहा है। '

जिनेवा। चार गैर सरकारी संगठनों की ओर से द इंटरनेशनल फेलोशिप आफ रिकांसिलिएशन (आईएफआर) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् को आगाह किया है कि तिब्बत में सांस्कृतिक संहार हो रहा है।

यह चेतावनी संगठन के प्रवक्त उरगेन तेनजिन ने अपने वक्तव्य में दी है। इसमें उन्होंने कहा है, ''तिब्बती जनता अब एक तरह के ' सांस्कृतिक संहार' से दोचार हो रही है जो विश्लेषकों के अनुसार दुनिया की छत कहे जाने वाले इस क्षेत्र में हो रहा है। तथाकथित विकास परियोजनाओं के चलते चीनी जनसंख्या के तिब्बती भूमि पर स्थानांतण को बल मिला है जिससे तिब्बती पठार के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और क्षेत्र के व्यापक प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर निकाला भी जा रहा है।'

चीन की सरकार चीनी नागरिकों को बड़े पैमाने पर तिब्बत में स्थानांतरित कर रही है जिसके चलते वहां के लोगों के समक्ष एक नस्ल के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखना भी चुनौती बनता जा रहा है। तिब्बती अपनी मातृ भूमि में ही अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। इन गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त वक्तव्य में परिषद् से मांग की गई है कि इस संबंध में सकारात्मक पहल की जाये क्योंकि इसके लिये तुरंत जांच करने वाले संयुक्त मिशन को तिब्बत भेजने की आवश्यकता है।

इससे पहले मौजूदा चीन में ' अल्पसंख्यकों' के मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक फोरम में गंभीर परिचर्चा हुई। तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान की कार्यकारी निदेशक (यूरोप) सेरिंग जांपा ने तिब्बत का पक्ष रखा। इस परिचर्चा 'उठते मानवाधिकार मुद्दे : चीन में अल्पसंख्यक' का आयोजन अल्पसंख्यक अधिकार समूह (एम आर जी आई) तथा संकटग्रस्त लोगों के समाज (एस टी पी) ने किया था। इसमें चीन में मानवाधिकार की कार्यक्रम अधिकारी केरोल वांग तथा वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस की अध्यक्ष राबिया कदीर ने भी विचार रखे।

एमआरजीआई तथा चीन में मानवाधिकार संगठन द्वारा तैयार इस रपट में कहा गया है : ''इस नीति के उद्देश्य के तहत जिसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तत्व शामिल हैं, अल्पसंख्यक निरंतर खतरे में हैं। यह खतरा आधिकारिक प्रतिबंधों एवं अन्य कई कारणों से है। स्वायत्तशासी क्षेत्र की शहरी जनसंख्या में हान चीनी नागरिकों का दबदबा है जिससे अल्पसंख्यकों के लिये अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखना मुश्किल हो गया है।''

उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार परिषद् ने पिछले दिनों एक फ्रांसीसी एनजीओ का लिखित वक्तव्य जारी किया था। इसमें कहा गया था : ''चीन के पूर्व राष्ट्रपति ने जब तिब्बत को रेल लाइन के निर्माण को 'राजनीतिक निर्णय' किया तो अब सवाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष है कि तिब्बत में सांस्कृतिक संहार को रोकने के लिये तत्काल क्या पहल की जाये। अन्यथा मानवाधिकार परिषद् दुनिया की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रही है। दुनिया को अब चीनी नागरिकों के तिब्बत में जनसंख्या स्थानांतरण के मानवाधिकार आयाम को समझना होगा ... इससे पहले कि बहुत देर हो जाये।''

चीन ने 1950 वाले दशक में तिब्बत पर कब्जा जमाने के तुरंत बाद तिब्बत के खम और आम्दो प्रांतों को अपने आसपास वाले युन्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसू प्रांतों में मिला दिया था। इसके साथ ही वहां बहुत बड़े पैमाने पर चीनी नागरिकों को बसाकर उन्हें चीनी रंग में रंग दिया गया। बाकी बचे हुए तिब्बत (टार) में भी पिछले कई साल से यह अभियान शुरू हो चुका है। तिब्बत में पिछले साल नई रेलवे लाइन बिछाने के बाद तिब्बती नागरिकों को वहां लाकर बसाने के अभियान ने गति पकड़ ली है।

ग्लेशियरों के पिघलने से चीन में जल संकट बढेगा : ग्रीनपीस

लंदन। पर्यावरण समूह ग्रीनपीस ने आगाह किया है कि तिब्बत में ग्लेशियर पिघलने और उनके क्षेत्र के सिकुड़ने से चीन में जल संकट गहरा सकता है। ये ग्लेशियर चीन के एक बड़े हिस्से में जलापूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

ग्रीनपीस के अनुसार पर्यावरणीय बदलाव को देखते हुए निकट भविष्य में ग्लेशियर अधिक गर्म होंगे और पिघलेंगे। इसके बाद नदियों में पानी की कमी होगी।

' द इंडिपेंडेंट' ने ग्रीनपीस के हवाले से इस बारे में सिचुआन प्रांत का उदाहरण दिया है। यह प्रांत जल स्रोत के लिये बहुत कुछ तिब्बती क्षेत्र पर निर्भर करता है। जियुचाइगोउ से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित कांडिंग में ग्लेशियरों की घाटी है जिस पर बढ़ते तापमान का बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है।

ग्रीनपीस का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समूचे चिंघाई तिब्बती क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बर्फ गायब हो रही है। इसका असर नदियों में जल की मात्रा तथा स्तर पर पड़ा है।

चीन के सरकारी अनुसंधान आंकड़े भी दर्शाते हैं कि ग्लोबल वार्मिग के कारण इस भूभाग के ग्लेशियर सात प्रतिशत सालाना की दर से पिघल रहे हैं। ग्रीनपीस के बीजिंग कार्यालय के ली यान ने कहा कि चीन के कुल ग्लेशियरों में इस क्षेत्र के ग्लेशियरों का हिस्सा 47 प्रतिशत है।

इन पहाड़ों से येलो रिवर तथा यांग्त्सी तथा अनेक अन्य नदियों को पानी मिलता है जो चीन के साथ साथ दक्षिण एशिया के लाखों लोगों को जल उपलब्ध कराती हैं।

चिंघाई तिब्बत पठार का क्षेत्र लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है जो चीन की भूमि का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। यह क्षेत्र समुद्र तट से औसतन लगभग 4,000 मीटर की उंचाई पर है। यान ने दावा किया कि ग्लेशियरों के पिघलने से येलो नदी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ पहले ही यह चेतावनी दे चुके हैं कि तिब्बत से चीन द्वारा जंगलों की कटाई तिब्बत और चीनी पर्यावरण के लिए घातक होगी।

ग्रीनपीस ने एक अनुमान का जिक्र किया है जिसके अनुसार तिब्बत तथा आसपास के हिस्सों में स्थित ग्लेशियरों का 80 प्रतिशत हिस्सा 2035 तक पिघल सकता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघलेंगे।

तिब्बती धार्मिक अवशेष चीन की संपत्ति हैं : चीन

बीजिंग, 29 जुलाई रायटर्स समाचार एजेंसी ने सिन्हुआ संवाद समिति के माध्यम से किए गए इस चीनी दावे का समाचार दिया है कि तिब्बत में मौजूद पूजा के सभी धार्मिक अवषेष या मूर्तिया चीन देश की सम्पत्ति हैं।

चीन की इस पहल को तिब्बत में धर्म पर नियंत्रण की नयी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चीन अपने धार्मिक समूहों, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्मानुयायियों से हमेशा ही चिंतित रहा है और वहां 'अलगाव' की बात करने के आरोप में अनेक तिब्बती भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को जेल में डाला जा चुका है।

यहां उल्लेखनीय है कि 1966–79 की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान भी तिब्बत की सांस्कृतिक धरोहर को भारी नुकसान हुआ और माओवादी रेड गार्डों ने तिब्बत के अधिकांश धार्मिक प्रतीकों तथा विहारों को तबाह कर दिया था। इस विनाश लीला के दौरान तिब्बती मठों और परिवारों की कई बेशकीमती ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में इन चीजों को अंतर्राष्ट्रीय चोर बाजार में बेच दिया गया।

परमाणु बेस को संग्राहलय में बदलेगा चीन

बीजिंग। चीन ने उस परमाणु बेस को संग्राहलय में बदलने की घोषणा की है जहां उसने अपना पहला परमुाण बम तैयार किया था। सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ का कहना है कि यह बेस तिब्बत क्षेत्र में चिंघाई प्रांत में है। चीन ने इस बेस को गैर वर्गीकृत कर दिया है ताकि यहां पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इस बेस का निर्माण 1958 में हुआ था और 1987 में इसे बंद कर दिया गया।

एक स्थानीय अधिकारी चुओ शुमिन ने कहा है,''यह बेस प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा। इसे चीन राष्ट्र की देशभक्ति भावना को प्रदर्षित करने वाले केंद्र के रूप में बदला जायेगा।'' चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1964 में किया। तीन साल बाद इसने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इस बेस में एक अनुसंधान प्रयोगशाला, नियंत्रण केंद्र, बिजली उत्पादन एवं संचार कक्ष हैं। सरकारी संवाद समिति के अनुसार इसे अब एक 'एटोमिक टाउन' के रूप में जाना जायेगा।

ग्रीनपीस का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समूचे चिंघाई तिब्बती क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बर्फ गायब हो रही है। इसका असर नदियों में जल की मात्रा तथा स्तर पर पड़ा है। चीन के सरकारी अनुसंधान आंकड़े भी दर्शाते हैं कि ग्लोबल वार्मिग के कारण इस भूभाग के ग्लेशियर सात प्रतिशत सालाना की दर से पिघल रहे हैं।

तिब्बत की कहानी -

1. चीन सरकार की धमकियों और दबाव के बावजूद दलाई लामा की आस्ट्रेलिया यात्रा के
2. दलाई लामा की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता श्री केविन रुड ने चीन सर
3. एयरटेल के रंगों में तिब्बती संगीत का रंग जोड़ने के धर्मशाला लॉच समारोह में तिब्बत
4. कनाडा के कंपन कॉटिनेंटल मिनरल्स द्वारा तिब्बत में खनिजों की चीनी लूट में सहयो
5. तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम को नई गति देने वाली संस्था फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत ने धर्मशा
6. तिब्बत की आजादी के आंदोलन के समर्थन में तिब्बती संगीत शिक्षक दोरजी सेरिंग ने
7. 7 जून को भारत तिब्बत सहयोग मंच ने राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन, हिंदू जागरण मंच
8. 2 मई को लंदन के स्टैन्फोर्ड आर्ट सेंटर ने तिब्बत फैस्टिवल का आयोजन किया।
9. स्वीडन में तिब्बत समर्थक संगठनों ने तिब्बत के समर्थन में 7 जून को एक प्रदर्शन कि
10. 7 जून को तिब्बत समर्थक प्रदर्शन में दो तिब्बती बच्चे तिब्बत का राष्ट्र ध्वज थामे हुए

—— कैमरे की जुबानी

दौरान प्रधानमंत्री जान हावर्ड ने उनके साथ 15 जून को मुलाकात की ।
कार की धमकियों की परवाह न करते हुए उनके साथ भेंट की।
ी संसद उपाध्यक्षा दोलमा ग्यारी और कंपनी के श्री भुल्लर । फोटो : फुरबू थिनले
ा के खिलाफ वेनकूवर में कंपनी एजीएम मीटिंग के दौरान तिब्बत समर्थकों का प्रदर्शन।
ला में अपना समर कैंप आयोजित किया। तिब्बती संसद के सामने संस्था के कार्यकर्ता।
14–15 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 48 घंटे तक संगीत पेश किया।
, कर्तव्य बोध ट्रस्ट और हिमालय परिवार के साथ तिब्बत के समर्थन में प्रदर्शन किया।

या।
।

(फ़ोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

स्कूल के रजत जयंती समारोह में मेहमान : दोस्ती का संबल

स्रोंगत्सेन भृकुटी बोर्डिंग हाई स्कूल का रजत जयंती समारोह

नेपाल के सर्वोत्तम स्कूलों की श्रेणी का तिब्बती स्कूल

इस स्कूल को तिब्बती और नेपाली जनता के मैत्री सेतु के रूप में जाना जाता है। नेपाल की राजकुमारी भृकुटी देवी तिब्बत के ऐतिहासिक और महान शासक स्रोगत्सेन की पत्नी थीं। उनके विवाह से दोनों देशों के बीच रिश्तों की ऊंचाई कई सदियों से बनी हुई है।

काठमांडो। स्रोंगत्सेन भृकुटी बोर्डिंग हाई स्कूल, काठमांडो ने अपनी रजत जयंती वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वीडन के संगठन एसओआईआर आईएम के पूर्व महासचिव स्टेफान हामस्ट्राम थे। इसके अलावा दानदाता संगठनों के प्रतिनिधि, 60 से अधिक विदेशी प्रायोजक, तिब्बती अधिकारी, अतिथि, अभिभावक एवं विद्यार्थीगण मौजूद थे। इस अवसर पर अनेक आयोजन हुए जो दिन भर चले।

इस विद्यालय की शुरुआत 1982 में किराये के एक भवन में हुई थी। आज इस आवासीय स्कूल में 682 विद्यार्थी तथा 66 अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी हैं। इस स्कूल को नेपाल में तिब्बती और नेपाली जनता के एक मैत्री सेतु के रूप में जाना जाता है। नेपाल की राजकुमारी भृकुटी देवी तिब्बत के ऐतिहासिक और महान शासक स्रोगत्सेन की पत्नी थीं। उनके विवाह ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को जो ऊंचाई दी उसका प्रभाव कई सदियों से बना हुआ है।

प्रधानाध्यापक भिक्षु जांपा फुंतसोक ने अतिथियों का स्वागत किया और विद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय सुविधाओं से वंचित तिब्बती बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर रहा है। उन्होंने उन शुरुआती दिनों को याद किया जब एक ही कमरे में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता था।

एसओआईआर . आईएम ने 1990 में कक्षाभवन, 1992 में छात्रावास भवन तथा 1994 में कर्मचारी आवास के लिये धन मुहैया कराया। इसके अलावा अलग भवन के लिये धन यूरोपीय संघ ने मुहैया कराया। फिलहाल इस स्कूल को नेपाल में सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक माना जाता है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट (एसएफटी) के उन सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था जिन्होंने चीन के खिलाफ एवरेस्ट के आधार शिविर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इन सदस्यों को जिनमें तेंनिज दोरजी शामिल है, को खातागे देकर सम्मानित किया। उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया।

लिश्टेंस्टाइन संसद ने तिब्बत समर्थक प्रस्ताव पारित किया

जिनेवा। लिश्टेंस्टाइन संसद ने 27 अप्रैल को समाप्त अपने तीन दिन के सत्र में तिब्बत संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह पहल चीन सरकार के सोलेमन प्रस्तुतीकरण के बावजूद की गई है।

तीन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिनमें प्रोग्रेसिव पार्टी की श्रीमती जोसी बिदरमेन, पेट्रियोटिक यूनियन के हेरी क्वादरर तथा फ्री लिस्ट की श्रीमती आंद्रा मट शामिल हैं, दो अप्रैल को संसद में तिब्बत पर एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था।

हेरी क्वादरर ने 25 अप्रैल को अपने साथी सदस्यों की ओर से से इस प्रस्ताव को संसद में रखा जिसे 18 सांसदों के समर्थन से स्वीकार कर लिया गया। छह सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया जबकि एक अनुपस्थित रहे। यह संसद इससे पहले जून 1996 में भी तिब्बत पर एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

लिश्टेंस्टाइन की संसद में 25 सदस्य हैं जो हर साल आठ से दस बार बैठक करते हैं।

लिश्टेंस्टाइन के सांसदों को यह प्रस्ताव पारित करने से रोकने के लिए चीन सरकार की ओर से भारी लॉबिंग की गई थी लेकिन इसका कोई बड़ा असर नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत के समर्थन में पारित तीन प्रस्तावों के अलावा 20 से अधिक देशों की संसद में तिब्बत के समर्थन में अब तक लगभग 50 बार प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा यूरोप की एक हजार से ज्यादा नगरपालिकाएं तिब्बत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित करने, अपने भवन पर तिब्बत का झंडा लगाने और सड़कों के तिब्बती नाम रखने के कदम उठा चुकी हैं।

फोटो : विजय क्रान्ति

तूरीन सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधि : विश्व में फैलता तिब्बत आंदोलन

तूरीन में तिब्बत मुक्ति के लिए सम्मेलन

तिब्बत की आजादी के मुद्दे तथा नयी रणनीति पर विचार विमर्श

तिब्बत की आजादी के लिये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इटली के तूरीन में 26 मई को आयोजित हुआ जिसमें तिब्बत की आजादी के मुद्दे तथा नयी रणनीतियों पर विचार विमर्ष किया गया। इस सम्मेलन में लगभग सौ वक्ता, अतिथि एवं प्रतिनिधि शामिल हुए।

सम्मेलन का आयोजन सीएसपीटी ने टिबेट कल्चर हाउस, टिबेट डेस्टीनेशन रांगज़ेन एंड आल्टरनेटिव टिबेटन (फ्रांस) के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का प्रायोजन इटली के श्रमिक संगठन सीआईएसएल आईएससीओएस ने किया।

इस सम्मेलन का आयोजन गत साल 19 सितंबर को वाशिंगटन तथा 23 दिसंबर को न्यूयार्क में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की तर्ज पर किया गया था।

सम्मेलन में अमेरिका, भारत, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्विटजरलैंड आदि यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तिब्बती स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इटली के श्रमिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा चीनी लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता वाई जिंगशेंग भी मौजूद थे।

इस अवसर पर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि चीन की वास्तविकता वह नहीं है जो सीसीपी दिखाती है। चीन में असमानता बढ़ रही है और व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। चीन के बहुतायत हिस्से में किसानों की स्थिति आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बदतर होती जा रही है। आर्थिक विकास से भी जीवन स्तर तथा अधिकतर श्रमिकों की कामकाजी परिस्थतियों में कोई सुधार नहीं हुआ है और मूल अधिकारों से लोगों को वंचित रखा जा रहा है।

ऐसी हालत में सामाजिक स्तर पर विरोध लगातार बढ़ा है जिसे चीन के अधिकारी भी स्वीकार कर चुके हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक आंदोलन फालुन दाफा के समर्थकों के अहिंसक विरोध, मुक्त श्रमिक संगठन स्थापित करने के लिए श्रमिकों की लड़ाई तथा तुर्किस्तान और दक्षिणी मंगोलिया में चीन के उपनिवेशी कब्जे के खिलाफ फिर संगठित हो रहे विरोध का भी जिक्र किया जाना चाहिए ।

अंतरराष्ट्रीय ढांचे में भी चीन की नीतियां आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य दृष्टिकोण से अधिकाधिक आक्रामक होती जा रही हैं। तिब्बत को लेकर चीन की नीतियों में गत कुछ वर्षो में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां तक कि कई कोणों से ये नीतियां अधिक कठोर ही हुई हैं। हान लोगों को तिब्बत क्षेत्र में बसाने का क्रम जारी है। इसी तरह तिब्बत के लोगों को अपने ही देश में हाशिए पर धकेला जा रहा है।

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव :

– एक ऐसे संगठित आजादी आंदोलन का समर्थन किया जााये जो तिब्बती लोगों के स्वतंत्र तिब्बत के सपने को वास्तविकता में बदल सके।

– तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर आधारित एक उचित कार्ययोजना तैयार की जाये जो दिसंबर 2006 तथा सितंबर 2006 में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के फैसलों के अनुरूप हो।

– तिब्बत पर कब्जे का विरोध कर रही सभी राजनीतिक तथा सामाजिक ताकतों को एक सूत्र में पिरोया जाये।

–चीन में फ्री ट्रेड यूनियन की स्थापना की जाये।

– सभी मुक्त राष्ट्रों से बीजिंग में होने वाले 2008 ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने को कहा जाये।

– संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान तथा दक्षिणी मंगोलिया के अवैध अधिग्रहण की निंदा करने का आग्रह किया जाये।

– यूरोपीय संघ से चीन के साथ बातचीत को तब तक बंद रखने को कहा जाये, जब तक कि चीन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू नहीं करता।

– तिब्बत तथा चीन में अमानवीय दंड की समाप्ति के लिये वैश्विक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून लागू किया जाये।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि चीन की वास्तविकता वह नहीं है जो सीसीपी दिखाती है। चीन में असमानता बढ़ रही है और व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। चीन के बहुतायत हिस्से में किसानों की स्थिति आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बदतर होती जा रही है।

तिब्बती केंद्र में रिचर्ड गेअर तिब्बती प्रशंसकों के साथ : भरोसेमंद दोस्त

तिब्बती स्वागत केंद्र में रिचर्ड गेअर

नेपाल में दलाई लामा का प्रतिनिधि कार्यालय फिर से शुरू करने पर संकट बरकरार

नेपाल में बहुत कुछ नया हो रहा है। नया संविधान लिखा जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को नये सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि तिब्बत की चिंता करने वाले सभी लोगों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण समय है।

काठमांडो हालीवुड अभिनेता रिचर्ड गेअर ने तिब्बती स्वागत केंद्र का दौरा किया। स्वागत केंद्र के निदेशक के अलावा केंद्र में हाल ही में तिब्बत से भागकर आये तिब्बती शरणार्थियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ अन्य तिब्बती अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने श्री गेअर को पारंपरिक स्कार्फ भेंट किए। गेअर ने हाल ही में केंद्र में आये लगभग हर नये तिब्बती से हाथ मिलाया जिनमें एक पूर्व राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं जो उनसे मिलने के लिये कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे।

नेपाल की तीन दिन की यात्रा पर आये गेअर ने कहा कि वे अपने कुछ पुराने तिब्बती दोस्तों से मिलने तथा नेपाल में बदलते हालात को देखने के लिये आये हैं। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल में तिब्बत की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए।

नेपाल में मौजूदा सबसे बड़ा मुद्दा यहां परम पावन दलाई लामा का प्रतिनिधि कार्यालय फिर से शुरू करना भी है। 2005 में इसे चीन के दबाव में नेपाल सरकार ने बंद कर दिया था। दुनिया भर से आने वाली अपीलों के बावजूद नेपाल सरकार ने इसे फिर से खोलने की अभी अनुमति नहीं दी है।

पूर्व नेपाल नरेश की सरकार ने यह कहते हुए इस कार्यालय को 2005 में बंद कर दिया था कि इस कार्यालय को चार दशक से बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा था। लेकिन तिब्बत समर्थकों का कहना है कि नेपाल सरकार की यह दलील बहुत कमजोर है क्योंकि इस चार दशक के दौरान खुद नेपाल सरकार इस कार्यालय के साथ संपर्क बनाए हुए थी। तिब्बतियों का मानना है कि यह पहल चीन सरकार के दबाव में की गई।

इस अवसर पर गेअर ने तिब्बती मीडिया से भी संक्षिप्त बातचीत की। उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछे जाने पर गेअर ने कहा, ''तिब्बत के आंदोलन के लिये यह बेहद संकट का दौर है। मेरा मानना है कि दुनिया भर में बहुत अच्छे लोग हैं जो तिब्बत एवं तिब्बती लोगों के बारे में सोचते हैं . . . धर्मशाला से लेकर यहां काठमांडो तक तिब्बती आंदोलन से जुड़े अच्छे लोग हैं। मेरा मानना है कि इन सभी को एकसाथ जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नेपाल में हो रहे बदलाव से हम सभी को सम्बद्ध होना चाहिए। नेपाल में बहुत कुछ नया हो रहा है। नया संविधान लिखा जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को नये सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि तिब्बत की चिंता करने वाले सभी लोगों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण समय है।''

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी पर्यटक की भांति यह यात्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका उद्देश्य तिब्बती मित्रों से मिलना है। वे यहां दो उद्देश्य लेकर आये हैं। एक उद्देश्य नेपाल की नयी सरकार में शामिल होने वाले लोगों से मुलाकात करना है। उन्होंने कहा कि वे नेपाल को लेकर और हिमालय क्षेत्र को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन उनकी पहली चिंता तिब्बती हैं इसलिये ही वे इस स्वागत केंद्र में आयें हैं ताकि देख सकें कि यह कैसे काम कर रहा है।''

गेअर ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि यह केंद्र सही ढंग से काम कर रहा है। गेअर तिब्बतियों एवं दलाई लामा के सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों से एक हैं। हालिवुड के सबसे लोकप्रिय स्टार होने के बावजूद श्री गेअर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि लेते हैं। वह तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा के गहरे प्रशंसक और मित्र भी हैं। रिचर्ड गेअर दुनिया की उन गिनी चुनी लोप्रिय हस्तियों में से हैं जिन्होंने चीनी उपनिवेशवाद के पैरों तले कुचली तिब्बती जनता की आजादी के लिए अपने प्रोफेशनल और आर्थिक हितों की परवाह किए बिना आवाज़ बुलंद की।

(फायुल संवाददाता तेनज़िन चोफेल की रिपोर्ट पर आधारित)

रायल अल्बर्ट हाल की आलोचना

लंदन। चीन के सूचना मंत्री काइ वू की अल्बर्ट हाल की यात्रा के दौरान तिब्बती लोगों तथा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। चीन के मंत्री इस प्रतिष्ठित हाल में आयोजित एक प्रदर्शनी ' तिब्बत थ्रू द लेंस' को देखने आये थे। दरअसल स्टूडेंट फार ए फ्री तिब्बत यूके (एसएफटी) तथा टिबेटन यूथ यूके आदि संगठनों के लिये अल्बर्ट हाल की यह पहल किसी हैरानी करने वाले कदम से अलग नहीं थी क्योंकि आम तौर पर वहां इस तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होते। इस प्रदर्शनी में तिब्बत पर आधारित चित्रों का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन रायल अल्बर्ट हाल ने चीन की सरकार के साथ सहयोग से किया था।

टिबेटन यूथ यूके के निदेशक करमा चुरात्सांग ने कहा, ''चीन की सरकार की इस प्रदर्शनी में स्वस्थ एवं मुस्कराते तिब्बतियों को उनकी पारंपरिक पोषाकों में दिखाया गया है। प्रदर्शनी में कुछ भी नया नहीं है। किसी मनोहारी स्थान पर पारंपरिक पोषाकों में खड़े करके तिब्बतियों के ये फोटो दीवार पर टंगने वाले कैलेंडरों आदि में दिखाई दे ही जाते हैं। वास्तव में चीन की नीति तिब्बतियों को अपने ही देश में सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में हाशिये पर धकेल देने की है। अपनी इस चाल को छिपाने के लिए चीन सरकार इस तरह की फोटो प्रदर्शनियां लगाती है।''

एसएफटी यूके की एलिस स्पेलर ने कहा, ''चीन सरकार इस तरह की प्रदर्शनियों का इस्तेमाल तिब्बत पर अपने उपनिवेशवादी कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश में करती है।'' उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि ब्रिटेन का यह प्रतिष्ठित संस्थान भी चीन के इस प्रोपगेंडा के चक्कर में आ गया। उन्होंने कहा कि, ''यह प्रदर्शनी तिब्बत की वास्तविकता को नहीं दिखाती है। प्रदर्शनी में तिब्बत को 'प्राचीन इतिहास, सौंदर्य एवं जादू की भूमि' के रूप में दिखाया गया है जबकि वहां रहने वाले तिब्बती लोगों के लिये यह 'विध्वंस, उत्पीड़न एवं भय की भूमि' बनी हुई है।''

इस प्रदर्शनी में तिब्बतियों को कंप्यूटर, मोबाइल फोन एवं रेडियो आदि के साथ दिखाया गया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि चीन तिब्बत का विकास कर रहा है। कई फोटो तिब्बत के स्कूली बच्चों के भी है यह अलग बात है कि 2004 में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा पर विषेष दूत ने कहा था कि तिब्बत में साक्षरता की दर मात्र 40 प्रतिशत ही है।

इन संगठनों ने इस संबंध में रायल अल्बर्ट हाल के निदेषक को पत्र भी भेजा है।

विस्कानसिन प्रतिनिधियों ने तिब्बत प्रस्ताव दलाई लामा को सौंपा

परम पावन दलाई लामा के साथ एक व्यक्तिगत बैठक में विस्कानसिन के 'मुक्त तिब्बत' प्रस्ताव पर विचार किया गया ताकि तिब्बती लोगों को स्वतंत्रता के लिये चीन पर दबाव बनाया जा सके।

प्रतिनिधि स्पेंसर ब्लेक तथा जोई पारिसी को दलाई लामा से मिलने के लिये आमंत्रित किया गया था। उन्होंने राज्य की विधाानसभा के संयुक्त प्रस्ताव 22 को दलाई लामा को सौंपा जिसे विस्कानसिन विधानसभा ने हाल ही में पारित किया था।

इस प्रस्ताव में विस्कानसिन जनप्रतिनिधियों ने तिब्बती लोगों की आजादी का आह्वान करते हुए उनकी राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विसकानसिन में अनेक तिब्बती ऐतिहासिक धरोहरें हैं और उनका राज्य तिब्बत की आजादी का लंबे समय से समर्थक रहा है।

तिब्बती समारोह में शामिल हुई जोना

लंदन। लंदन में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि के विदाई तथा स्वागत समारोह में अन्य हस्तियों के साथ साथ ब्रिटेन की प्रमुख अभिनेत्री जोना लुमले भी शामिल हुईं। इस कार्यक्रम का आयोजन तिब्बत कार्यालय लंदन तथा ब्रिटेन में तिब्बती समुदाय ने संयुक्त रूप से किया था।

इस कार्यक्रम में दलाई लामा की निवर्तमान प्रतिनिधि श्रीमती केसांग वाई ताकला को विदाई दी गई और सेरिंग ताशी का स्वागत किया गया। ताशी को उत्तरी यूरोप, पौलेंड तथा बाल्टिक देशों के लिये परम पावन दलाई लामा का नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

ब्रूसेल्स में तिब्बती फिल्म समारोह

तिब्बत समर्थक समूह बेल्जियम 'ले एमिस डू टिब्बेट ' ने तिब्बत एवं हिमालय के बारे में फिल्मों का एक समारोह ब्रूसेल्स में आयोजित किया। इस समारोह में जिन फिल्मों का प्रदर्षन किया गया उनमें ड्रीमिंग ल्हासा, बोकर रिंपोछे, टिब्बेटस स्टोलन चाइल्ड, ए मेन काल्ड नोमाड शामिल हैं।

इस अवसर पर फ्रांस के 'तिब्बती सुलेखविद' जिग्मे दोउछे ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने उन्हें कलात्मक तिब्बती शब्द एवं वाक्य लिखते देखा। अनेक लोगों ने आईसीटी तथा ले एमिस डू टिब्बेट के सूचना पट्टों में भी रुचि दिखाई।

एसएफटी यूके की एलिस स्पेलर ने कहा ''चीन सरकार इस तरह की प्रदर्शनियों का इस्तेमाल तिब्बत पर अपने उपनिवेशवादी कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश में करती है। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि ब्रिटेन का यह प्रतिष्ठित संस्थान भी चीन के इस प्रोपगेंडा के चक्कर में आ गया।

भारत–चीन सीमा वार्ता के खिलाफ प्रदर्शन : न्याय की जरूरत

भारत–चीन में सीमा वार्ताओं पर चेतावनी के लिए प्रदर्शन तथा रैली

प्रदर्शनकारियों ने इस प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा पर यह कहते हुए विरोध जताया भारत और तिब्बत की सीमा के बारे में कोई आपसी समझौता करने का अधिकार केवल भारत और तिब्बत को है। इसे भारत और चीन की सरकारें आपस में तय नहीं कर सकतीं।

धर्मशाला के तिब्बती नागरिकों ने भारत एवं चीन के बीच सीमा वार्ताओं के खिलाफ रैली निकाली। रैली का आयोजन क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस (आरटीवाईसी) की अगुवाई में किया गया।

इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भिक्षु, भिक्षुणियां तथा आम तिब्बती शामिल हुए। रैली मुख्य मैकलोड चौराहे से शुरू होकर त्सुगला खांग पहुंची जहां एक जनसभा आयोजित की गई।

इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 400 से अधिक तिब्बतियों ने तिब्बती युवा कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन किया। ये लोग चीन के उप विदेश मंत्री एवं विशेश प्रतिनिधि देई बिंगुओ की भारत यात्रा तथा चीन – भारत सीमा वार्ताओं का विरोध जता रहे थे। इस आयोजन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई जहां प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग तक प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा और तिब्बती राष्ट्रगान गाया। आरटीवाईसी के अध्यक्ष पेंपा तेरिंग ने केंद्रीय टीवाईसी का वक्तव्य पढ़ा।

उल्लेखनीय है कि चीन के उप विदेश मंत्री दाई बिंगुओ के नेतृत्व में चीन सरकार के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सीमा वार्ताओं के लिये भारत आया। इस दल ने भारत के विशेश प्रतिनिधि एम के नारायणन से मुलाकात की।

प्रदर्शनकारियों ने इस प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा पर यह कहते हुए विरोध जताया भारत और तिब्बत की सीमा के बारे में कोई आपसी समझौता करने का अधिकार केवल भारत और तिब्बत को है। इसे भारत और चीन की सरकारें आपस में तय नहीं कर सकतीं। उन्होंने चीन की सरकार से मांग की कि वह पंचेन लामा तथा तुलकू तेनजिन को तुरंत रिहा करे।

तिब्बती कला प्रदर्शनी

नयी दिल्ली। तिब्बती कलाकारों की पेंटिग्स की एक नयी प्रदर्षनी 'वज्र–विज़न' राष्ट्रीय राजधानी के इंडिया हेबीटाट सेंट की ओपन पाम कोट गैलरी में आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने किया और इसे एक अनूठी प्रदर्शनी बताया।

पांच दिन की इस प्रदर्षनी में क्लासिक्ल से लेकर समकालीनता के दायरे में बिखरी तिब्बती कला की अनूठी झांकियां सामने आईं।

तिब्बती माडर्न आर्ट की एक विशेषता यह भी है कि यह दुनिया भर में चले माडर्न आर्ट आंदोलन से शयद ही कोई साम्य रखती है। ऐसा माना जाता है कि तिब्बत में माडर्न आर्ट जैसी कोई चीज रही ही नहीं लेकिन कलाकारों ने अपने काम में सभ्यता के देशांतर –गमन को खूबसूरती से उकेरा।

प्रदर्षनी में जिन कलाकारों के काम को रखा गया उनमें अंग सांग, पेंपा गाडे, सेतेन ग्युरमे, सेरिंग नियानदाक, सोनम सेरिंग, केल्त्से तथा ग्या बी लामा शामिल हैं। इनमें से अधिकतर कलाकारों का जन्म ल्हासा में हुआ था और वे 'गेदुन छोफेल आर्टिस्ट गिल्ड' के अंग रहे हैं। वे उन कलाकारों में से हैं जो चीनी दमन से तंग आकर समय–समय पर जान पर खेलकर तिब्बत से भागते हैं और भारत में शरण लेने के लिए आते रहे हैं। हर साल 2000 से 4000 के बीच तिब्बती नागरिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत से भागकर विदशों में शरण लेते हैं।

इन कलाकारों में से अधिकतर का जन्म 1960 से 1970 के संकटकालीन समय में हुआ। कलाकारों की खासियत यही है कि जड़ों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बदलते समय एवं धारणाओं पर निगाह रखी है। इनमें से कई कलाकार अपने काम को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नेपाल, तिब्बत, चीन, मलेशिया एवं जापान में प्रदर्शित कर चुके हैं।

एक और बात जो तिब्बती कलाकारों को दूसरों से अलग करती है, वह है उनकी कला पर बौद्ध प्रभाव। प्रदर्शनी का प्रायोजन यास्मीन डिजाइनर्स ने किया।

तिब्बती पत्रिका साप्ताहिक हुई

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती समुदाय के दो प्रमुख समाचार पत्रों में से एक बोद–कई–बांगछेन (तिब्बत एक्सप्रेस) अब साप्ताहिक प्रकाशित होगा। लगभग 17 देशों में पहुंच रखने वाला यह समाचार पत्र अब तक दस दिन में एक बार प्रकाशित होता था। इससे पहले सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा प्रकाशित बोद–मि–रवांग (या तिब्बती आजादी) ही एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्र था।

तिब्बत एक्सप्रेस का प्रकाशन खावा कारपो तिब्बत कल्चर सेंटर करता है। इसके साप्ताहिक संस्करण का लोकार्पण सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में किया गया। यह कार्यशाला मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित की गई।

मुंडगोड स्थित इस केंद्र की नवस्थापित शाखा तिब्बत एक्सप्रेस का वही संस्करण स्थानीय प्रेस से प्रकाशित करती है ताकि डाक वितरण में देरी के कारण समाचार पत्र के पहुंचने में देरी नहीं हो।

यह सेंटर तिब्बत से जुड़े समाचारों एवं विश्लेषण पर आधारित एक वेबसाइट खावाकारपो डाट आर्ग भी चलाता है। तीन दिन की इस कार्यशाला का उद्घाटन सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सूचना सचिव थुबतेन सांफेल ने किया। तिब्बत के स्वतंत्रता आंदोलन में तिब्बती पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं के अलावा निर्वासन में इंटरनेट पत्रिकाओं की संख्या भी अच्छी है।

दलाई लामा का विश्वास : दुनिया में होगी शांति

पुणे, 26 मार्च तिब्बत के निर्वासित शासक और शीर्ष धर्मगुरू परम पावन दलाई लामा ने बहु धर्म एवं बहु समुदायों के प्रति भारत की सहनशीलता की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि समूची दुनिया में शांति एवं सद्भाव होगा। वे भगवान बुद्ध की 2550वीं वर्षगांठ पर प्रवचन कर रहे थे।

लगभग 25,000 लोग उनके उद्बोधन को सुनने के लिये इकट्ठा हुए।

दलाई लामा ने कहा कि भारत एक पवित्र देश है और दुनिया इसकी विविधि संस्कृति के लिये इसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि शेष दुनिया में समुदायों एवं धर्मों में मतभेद के इस दौर मे केवल भारत ही ऐसा देश है जहां अनेक धर्म एवं समुदायों के लोग शांति सद्भाव के साथ रह रहे हैं।

दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते भारतीय : प्रेम का रिश्ता

धर्मशाला के भारतीयों ने दलाई लामा की दीर्घायु के लिये प्रार्थनाएं कीं

हज़ारों लोगों ने अनूठे समारोह में भाग लिया

धर्मशाला। तिब्बत के निर्वासित शासक और धर्मगुरू परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु की कामना करते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय हिंदु समाज ने यहां विशेष प्रार्थनाएं की। श्री अजय मनकोटिया के नेतृत्व में भारत तिब्बत मैत्री एसोसिएशन की अगुआई वाली विशेष आयोजन समिति ने इस दो दिवसीय आयोजन में हरिद्वार गायत्री परिवार की सेवाएं लीं।

गायत्री परिवार के पुजारियों ने भारतीयों की ओर से आयोजित इस विशाल पूजा में अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप किया। इस उपलक्ष्य में दो दिन का विशेष अखंड जप एवं गायत्री हवन किया गया। इस आयोजन में स्वंय दलाई लामा भी उपस्थिति थे। इसके अलावा हजारों तिब्बतियों एवं गैर तिब्बतियों ने पूजा पाठ एवं मंत्रोच्चार में भाग लिया।

परम पावन दलाई लामा ने भारतीय समाज की एकात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि लगभग आधी सदी से भारतीय एवं तिब्बती समुदाय प्रेम भाव से रह रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व एवं बौद्ध मत में घनिष्ठ रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि यह भाइयों–बहनों का संबंध है। इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती सरकार के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। भारत तिब्बत सहयोग मंच, टैक्सी यूनियन, आटो रिक्शा यूनियन, व्यापार मंडल, गोरखा एसोसिएषन तथा स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रधान भी इस आयोजन में शामिल हुए।

परम पावन दलाई लामा ने भारतीय समाज की एकात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि आधी सदी से भारतीय एवं तिब्बती समुदाय प्रेम भाव से रह रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व एवं बौद्ध मत में घनिष्ठ रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि यह भाइयों–बहनों का संबंध है।

चीनी उत्पादों को लेकर अमेरिका में चिंता

राष्ट्रपति बुश ने समिति गठित की

चीन से आयात होने वाले विभिन्न उत्पादों को लेकर अमेरिकी बाजारों में चिंता फैल गई है। सरकार को कई तरह के चीनी सामान के संबंध में चेतावनी जारी करनी पड़ी है। बात यहां तक बढ़ी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता परखने के लिये समिति गठित की है।

राष्ट्रपति ने यह कदम चीन से आयातित मछलियों, समुद्री खाद्य तथा टायरों से लेकर खिलौनों तक बहुत से उत्पादों को लेकर अमेरिका में व्यक्त की जा रही चिंता के बाद उठाया है। वैसे राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि इस समिति का गठन सिर्फ चीनी सामान को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य सभी तरह के आयातित सामान की जांच करना है।

चीनी उत्पादों को लेकर अमेरिका में सवाल उठाये जा रहे हैं। सरकार को कई सामानों को लेकर चेतावनी जारी करनी पड़ी है और कुछ को बाजार से हटाना पड़ा है। उदाहरण के लिए 15 लाख खिलौना रेलगाड़ियों को बाजार से हटाने के आदेश दिये गये थे क्योंकि इनमें सीसे से बना पेंट लगा है जो बच्चों के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

उधर चीन ने विदेशी मीडिया पर आरोप लगाया है कि वह चीनी सामान की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। लेकिन सरकार ने साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि उसे अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। इस पूरे मामले में अमेरिका के खाद्य और दवा नियंत्रक (एफडीए) को भी आलोचना का सामना करना पड़ा है कि वह आयातित सामान की गुणवत्ता जांचने में सक्षम नहीं है।

राष्ट्रपति बुश ने नवगठित जांच समिति से कहा है कि वह अपनी रपट 60 दिन में उन्हें सौंपे। समिति की पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति बुश ने कहा, ''खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा गंभीर विषय है।'' समिति के प्रमुख ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी माइकल लीविट ने कहा, ''दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अमेरिकी चाहते हैं कि वे जो भी खरीदें वह सुरक्षित हो।''

लेकिन डेमोक्रेट सांसद चार्ल्स शूमर का कहना है कि यह समिति पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग है कि स्थाई रूप से एक 'इंपोर्ट जार' की नियुक्ति करनी होगी। व्हाइट हाउस को यह भी उम्मीद है कि उसके इस कदम से चीन नाराज नहीं होगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टोनी स्नो ने कहा, ''इसका निशाना चीन नहीं है। यह सामान्य व्यावसायिक कदम है। हम 150 से भी अधिक देशों से सामान आयात करते हैं और इसका उद्देष्य उन सब पर नजर रखना है।''

इस बीच चीनी उत्पादों को लेकर अमेरिका में सवाल उठाये जा रहे हैं। सरकार को कई सामानों को लेकर चेतावनी जारी करनी पड़ी है और कुछ को बाजार से हटाना पड़ा है।

उदाहरण के तौर पर 15 लाख खिलौना रेलगाड़ियों को बाजार से हटाने के आदेश दिये गये थे क्योंकि इनमें सीसे से बना पेंट लगा है जो बच्चों के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

इसी तरह एफडीए ने गत माह चीन से आने वाली पांच तरह की मछलियों और समुद्री खाद्य के आयात पर तब तक रोक लगाने लगाने की घोषणा की थी जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि चीन इनके उत्पादन में उन रासायनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं। चीनी टूथपेस्ट को लेकर भी अमेरिका में विवाद हो चुका है।

इस बीच अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर भी विवाद चल रहा है। चीन के साथ घटते अमेरिकी व्यापार का हवाला देते हुए अमेरिकी संसद ने कहा था कि ऐसी सूरत में अमेरिका को चीन से आयात पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसी संभावना है कि इस साल सिर्फ खाद्य सामग्री के आयात में ही 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

भूल सुधार

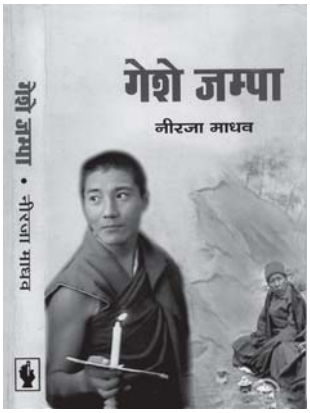

पिछले अंक में पुस्तक समीक्षा में गलती से छूट गई जानकारी इस प्रकार है:

उपन्यास : गेशे जम्पा
लेखिका : नीरजा माधव
पृष्ठ संख्या : 160
मूल्य : 200 रु.
प्रकाशक : सामयिक प्रकाशन, 3320–21 जटवाड़ा, दरियागंज, नई दिल्ली–2